



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242]

No. 242]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 29, 2012/ज्येष्ठ 8, 1934  
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 29, 2012/JYAISTA 8, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2012

सं. 29/2012-सीमा-शुल्क (एडीडी)

**सा.का.नि. 398(अ).**—अभिहित प्राधिकारी ने, चाईनीस ताईपेई, में 'मूलतः उदगमित या वहां से निर्यातित एसीटोन, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत आयात के मामले में अधिसूचना सं0 15/2/2011-डीजीएडी, तारीख 15 अप्रैल, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में तारीख 15 अप्रैल, 2011, के द्वारा प्रकाशित की गई थी के द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 33/2008-सीमाशुल्क, तारीख 11 मार्च, 2008, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सांकेतिक 174 (अ) तारीख 11 मार्च, 2008 के द्वारा प्रकाशित के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के संबद्ध में, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (5) तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरंभ की थी और अधिसूचना सं0 15/2/2011-डीजीएडी, तारीख 10 अप्रैल, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में तारीख 10 अप्रैल, 2012 के तहत, अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को वापस करने की सिफारिश की थी;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) तथा उपधारा (5) तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 20 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 33/2008-सीमाशुल्क, तारीख 11 मार्च, 2008, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सांकेतिक 174 (अ), तारीख 11 मार्च, 2008 के द्वारा प्रकाशित हुई थी, को उन बातों के सिवाय जो ऐसे विखंडन से पूर्व की गई है या जिन्हें करने का लोप किया गया है, में संशोधन करती है, अर्थातः-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रम सं0 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा;
- (ii) क्रम सं0 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा;
- (iii) क्रम सं0 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा;
- (iv) क्रम सं0 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा;
- (v) क्रम सं0 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा।

[फा. सं. 354/65/2007-टीआरयू(पार्ट-1)]

राजकुमार दिग्वजय, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना 33/2008-सीमाशुल्क, तारीख 11 मार्च, 2008 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सार्कारी नं0 174 (अ), तारीख 11 मार्च, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th May, 2012

**No. 29/2012-Customs (ADD)**

**G.S.R. 398(E).**—Whereas, the designated authority vide notification No. 15/2/2011-DGAD, dated the 15<sup>th</sup> April, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 15<sup>th</sup> April, 2011, had initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of Acetone, falling under Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, Chinese Taipei, imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 33/2008-Customs, dated the 11<sup>th</sup> March, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 174 (E), dated the 11<sup>th</sup> March, 2008, and had recommended withdrawal of the said anti-dumping duty *vide* notification No. 15/2/2011-DGAD, dated the 10<sup>th</sup> April, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 10<sup>th</sup> April, 2012,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of

Finance (Department of Revenue), No. 33/2008-Customs, dated the 11<sup>th</sup> March, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 174 (E), dated the 11<sup>th</sup> March, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such amendment, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (i) Sl. No. 1 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) Sl. No. 2 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iii) Sl. No. 3 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iv) Sl. No. 4 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (v) Sl. No. 5 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F.No. 354/65/2007-TRU(Pt.-I)]

RAJKUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

**Note:**—The principal notification No. 33/2008-Customs dated the 11<sup>th</sup> March, 2008, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 174 (E), dated the 11<sup>th</sup> March, 2008.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2012

सं. 30/2012 सीमा-शुल्क (एडीडी)

**सा.का.नि. 399(अ).**—अभिहित प्राधिकारी, यूरोपियन संघ (जिसे इसके बाद विषयगत देश कहा गया है) में मूलतः उत्पादित या वेहा से निर्यातित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उपशीर्ष 292141 के अंतर्गत आने वाले एनीलीन (जिसे इसके बाद विषयगत माल कहा गया है) के आयात के भागले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 13 अप्रैल, 2012 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं 14/39/2010-डीजीएडी, तारीख 13 अप्रैल, 2012 में इस निर्णय पर पहुंचे थे कि:-

- (क) संबद्ध माल भारतीय बाजार में प्रवेश कर रही है संबद्ध देश से सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया था, जिसके कारण पाठन हुआ था;
- (ख) घरेलू उद्योग को संबद्ध माल पर वास्तविक क्षति हुई थी; और
- (ग) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई थी और यह क्षति संबद्ध देश से उदगमित या निर्यातित पाठित आयातों के कारण हुई थी;

और संबद्ध देश में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये गए संबद्ध माल के आयातों पर निश्चयात्मक प्रतिपाठन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क टैरिफ (पाठित वरतुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाठित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) के साथ पठित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अभिहित

प्राधिकारी के पूर्वोक्त नि ष्ठर्षों के आधार पर, अद्योलिखित सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित देश में उदगमित, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए, ऐसे मालों पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्ष के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, और जिनकी विशिष्टता उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से, उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, तो उक्त सारणी के स्तंभ (11) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित करेंसी और उक्त सारणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रति मापन इकाई में व्यक्त, उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में इंगित संदर्भ राशि के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है।

### सारणी

| क्रम सं० | उपशीर्ष | माल का विवरण | विशिष्टता | उदगम देश                       | देश का निर्यातक                | उत्पादक | निर्यातक | राशि   | इकाई                   | करेंसी |
|----------|---------|--------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|---------|----------|--------|------------------------|--------|
|          | (2)     | (3)          | (4)       | (5)                            | (6)                            | (7)     | (8)      | (9)    | (10)                   | (11)   |
| 1        | 292141  | एनीलीन       | कोई       | यूरोपियन संघ                   | यूरोपियन संघ                   | कोई     | कोई      | 110.72 | मीट्रिक टन/अमरीकी डालर |        |
| 2        | 292141  | एनीलीन       | कोई       | यूरोपियन संघ के सिवाय अन्य देश | यूरोपियन संघ के सिवाय अन्य देश | कोई     | कोई      | 110.72 | मीट्रिक टन/अमरीकी डालर |        |
| 3        | 292141  | एनीलीन       | कोई       | यूरोपियन संघ के सिवाय अन्य देश | यूरोपियन संघ                   | कोई     | कोई      | 110.72 | मीट्रिक टन/अमरीकी डालर |        |

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष तक, (यदि उसका खंडन, अधिकांत और संशोधन न किया जाये) जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी रहेगा और भारतीय करेंसी में संदेय होगा।

**स्पष्टीकरण :** इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू विनिमय दर वह दर होंगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दित की गई है और विनिमय दर के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/335/2011-टीआरयू]  
राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th May, 2012

No. 30/2012-Customs (ADD)

**G.S.R. 399(E).**—Whereas, in the matter of import of Aniline (hereinafter referred to as the subject goods), falling under sub-heading 292141 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said Customs Tariff Act), originating in, or exported from European Union (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority, vide its final findings No. 14/39/2010-DGAD, dated the 13<sup>th</sup> April, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 13<sup>th</sup> April, 2012, had come to the conclusion that-

- (a) the subject goods had entered the Indian market from the subject countries below associated normal values, thus resulting in dumping of the subject goods;
- (b) the domestic industry had suffered material injury in respect of the subject goods; and
- (c) the material Injury to the domestic industry had been caused due to dumped imports of the subject goods from the subject countries.

and had recommended imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from, the subject countries.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes on the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, the specification of which is specified in the corresponding entry in column (4), falling under sub-heading of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5), and exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (6), and produced by the  
1926 RLJ/12-2

producers as specified in the corresponding entry in column (7), and exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (8), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (9), in the currency as specified in the corresponding entry in column (11) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10) of the said Table.

TABLE

| Sl.<br>No | Sub-<br>heading | Description<br>of goods | Specification | Country/territory<br>of origin              | Country/territory<br>of exports                | Producer | Exporter | Amount | Unit of<br>measurement | Currency  |
|-----------|-----------------|-------------------------|---------------|---|--|----------|----------|--------|------------------------|-----------|
| (1)       | (2)             | (3)                     | (4)           | (5)   | (6)  | (7)      | (8)      | (9)    | (10)                   | (11)      |
| 1         | 292141          | Aniline                 | Any           | European Union                              | European Union                                 | Any      | Any      | 110.72 | MT                     | US dollar |
| 2         | 292141          | Aniline                 | Any           | European Union                              | Any country<br>other than<br>European<br>Union | Any      | Any      | 110.72 | MT                     | US dollar |
| 3         | 292141          | Aniline                 | Any           | Any country<br>other than<br>European Union | European<br>Union                              | Any      | Any      | 110.72 | MT                     | US dollar |

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, amended and superseded earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

**Explanation.**—For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2012

सं. 38/2012 सीमा-शुल्क

**स.का.नि. 400(अ).**—केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 560 (अ), तारीख 31 अगस्त, 2004 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 85/2004-सीमाशुल्क, तारीख 31 अगस्त, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थातः—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं0 49 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जायेंगी, अर्थातः—

| (1)   | (2)      | (3)   |
|-------|----------|---|
| “ 49क | 84181090 | घरेलू प्रकार के अलग बाहरी दरवाजे के साथ लगाया, संपीड़न प्रकार के संयुक्त फ्रिज-फ्रीजर.” |

[फा. सं. 354/213/2002-ट्रीआरयू (भाग-I)]

राज कुमार दिग्विजय, अवर सचिव

**टिप्पणी :** मूल अधिसूचना 85/2004-सीमाशुल्क, तारीख 31 अगस्त, 2004 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 560 (अ), तारीख 31 अगस्त, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं0 115/2011-सीमाशुल्क, तारीख 28 दिसम्बर, 2011 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 907 (अ), तारीख 28 दिसम्बर, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के द्वारा किया गया था।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2012

No. 38/2012-Customs

**G.S.R. 400(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.85/2004-Customs, dated the 31<sup>st</sup> August, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 560 (E), dated the 31<sup>st</sup> August, 2004, namely:-

In the said notification, in the TABLE, after S.No. 49 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

| (1)  | (2)      | (3)   |
|------|----------|---|
| “49A | 84181090 | Compression-type combined refrigerator-freezers, fitted with separate external doors, household type” |

[F. No. 354/213/2002- TRU (Pt.-I)]

RAJ KUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

**Note:**—The principal notification No. 85/2004-Customs, dated the 31<sup>st</sup> August, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), vide number G.S.R. 560 (E), dated the 31<sup>st</sup> August, 2004 and was last amended by notification No. 115/2011-Customs, dated the 28<sup>th</sup> December, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), vide number G.S.R. 907 (E), dated the 28<sup>th</sup> December, 2011.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2012

सं. 2/2012-सीमा-शुल्क (एस जी)

**साक्षात् 401(अ).**—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ़ (निर्धारण और संग्रहण रक्षोपाय शुल्क) नियम, 1997 के नियम 10 और 14 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ़ अधिनियम, 1975 (1975 की 51) की धारा 8ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2012-सीमाशुल्क (रक्षोपाय शुल्क), तारीख 17 जनवरी, 2012 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. 29 (अ), तारीख 17 जनवरी, 2012 के द्वारा प्रकाशित हुई थी, को उन बातों के सिवाय जो ऐसे विखंडन से पूर्व की गई है या जिन्हें करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[फा. सं. 354/1/2012-(टीआरयू)]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2012

No. 2/2012-Customs (SG)

**GS.R. 401(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 10 and 14 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) no. 1/2012- Customs (SG), dated the 17<sup>th</sup> January, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 29 (E), dated the 17<sup>th</sup> January, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 354/1/2012-TRU]

RAJ KUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2012

सं. 3/2012-सीमा-शुल्क (एस जी)

**सा.का.नि. 402(अ).**—जबकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) (जिसे इरामे इराके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 2917 35 00 के अंतर्गत आने वाले थालिक एनहाइड्राइड के आयात के संदर्भ में महानिदेशक (रक्षोपाय), भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 23 सितम्बर, 2011 सा.का.नि. 0 719 (अ), तारीख 23 सितम्बर, 2011 द्वारा प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्ष में इस निर्णय पर पहुंचे थे कि थालिक एनहाइड्राइड के संवर्धित आयातों से थालिक एनहाइड्राइड के घरेलू उद्योग के लिए बाजार विघटन का खतरा पैदा हो गया था और भारत में थालिक एनहाइड्राइड के आयातों पर अनंतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना अनिवार्य हो गया था;

और जबकि, महानिदेशक (रक्षोपाय) के पूर्वाक्ता निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 0 29 (अ) तारीख 17 जनवरी, 2012 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2012-सीमाशुल्क (एस जी) तारीख 17 जनवरी, 2012, तारीख 25 अगस्त, 2011 द्वारा संबद्ध माल पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया गया था;

और जबकि, महानिदेशक (रक्षोपाय) अपने अंतिम निष्कर्षों के आधार पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 0 263 (अ), तारीख 29 मार्च, 2012 में प्रकाशित इस निर्णय पर पहुंचे थे कि थालिक एनहाइड्राइड के संवर्धित आयातों से थालिक एनहाइड्राइड के घरेलू उद्योग के लिए बाजार विघटन का खतरा पैदा हो गया था और भारत में थालिक एनहाइड्राइड के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना अनिवार्य हो गया था इरालिए संबद्ध माल पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने की रिपोर्ट की गई थी;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली 1997 के नियम 12 और 14 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक (रक्षोपाय) के उक्त जांच पर विचार करने के पश्चात, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 2917 35 00 के अंतर्गत आने वाले थालिक एनहाइड्राइड पर, जब भारत में आयात तारीख 17 जनवरी, 2012 से 16 जनवरी, 2013 तक (दोनों दिनों सहित) किया जाये, 10 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से, रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करती है।

2. पाकिस्तान, चीन और थाईलैंड को छोड़कर, अधिसूचित विकासशील देशों पर उक्त अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (6) के खंड (क) के अंतर्गत थालिक एनहाइड्राइड के आयात पर यह अधिसूचना प्रभावी नहीं होगी।

[फा. सं. 354/1/2012-टीआरयू]

राजकुमार दिव्यजय, अकर सचिव

1926 4/7/12-3

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th May, 2012

No. 3/2012-Customs (SG)

**G.S.R. 402(E).**—Whereas, in the matter of import of Phthalic anhydride (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff item 2917 35 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said Act), the Director General (Safeguard), in preliminary findings, *vide* number G.S.R. 719 (E), dated the 23<sup>rd</sup> September, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 23<sup>rd</sup> September, had come to the conclusion that increased imports of Phthalic anhydride into India had caused and threatened to cause further serious injury to the domestic producers of Phthalic anhydride and it had necessitated the imposition of provisional safeguard duty on imports of Phthalic anhydride into India;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the Director General (Safeguard), the Central Government had imposed provisional safeguard duty on imports of the subject goods *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2012-Customs (SG), dated the 17<sup>th</sup> January, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 29 (E), dated the 17th January, 2012;

And whereas, the Director General (Safeguard) in its final findings *vide* number G.S.R. 263(E), dated the 29th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 29th March, 2012, had come to the conclusion that increased imports of Phthalic anhydride into India had caused and threatened to cause further serious injury to the domestic producers of Phthalic anhydride and it necessitated the imposition of safeguard duty on imports of Phthalic anhydride into India, and had recommended the imposition of safeguard duty on imports of the subject goods into India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8B of the said Act, read with rules 12 and 14 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, the Central Government after considering the said findings of the Director General (Safeguards), hereby imposes on Phthalic anhydride, falling under tariff item 2917 35 00 of the First Schedule to the said Act, when imported into India, a safeguard duty at the rate of 10% *ad valorem*, when imported from the 17th day of January, 2012 to 16<sup>th</sup> day of January, 2013 (both days inclusive).

2. Nothing contained in this notification shall apply to imports of Phthalic anhydride from countries notified as developing countries under clause (a) of sub-section (6) of section 8B of the said Act, other than Pakistan, China and Thailand.

[F. No. 354/1/2012-(TRU)]  
RAJ KUMAR DIGVIIJAY, Under Secy.

## अधिमूलना

नई दिल्ली, 29 मई, 2012

सं. 16/2012-सेवा-कर

**साकानि. 403(अ)**—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 द्वारा सेवा कर को लागू की गई केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 31, धारा 32 और धारा 32क से 32त तक के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “अधिनियम” कहा गया है) की धारा 94 की उपधारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेवा कर (मामलों का समझौता) नियम, 2012 है।

(2) ये वित्त अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं :-** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) का अध्याय 5 अभिप्रेत है;

(ख) “उत्पाद-शुल्क अधिनियम” से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) अभिप्रेत है;

(ग) “प्ररूप एससी (एसटी)-1” से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है; और

(ज) ऐसे शब्दों या पदों के, जो यहां प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या उत्पाद-शुल्क अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो इन अधिनियमों में हैं।

**3. आवेदन का प्ररूप और रीति :-** (1) अधिनियम की धारा 83 द्वारा सेवा कर को लागू की गई उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ड की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन प्ररूप एससी (एसटी)-1 में किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन, उसमें अन्तर्विष्ट सत्यापन और ऐसे आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले सभी सुसंगत दस्तावेजों पर निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे,—

(क) किसी व्यक्ति की दशा में, स्वयं व्यक्ति द्वारा या जहां व्यक्ति भारत में नहीं है, वहां संबंधित व्यक्ति द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा,

और जहां व्यक्ति अवयस्क है या अपना कामकाज करने में मानसिक रूप से असमर्थ है वहां उसके संखक द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(ख) हिन्दू अधिकृत कुटुंब की दशा में, ऐसे कुटुंब के कर्ता द्वारा और जहां कर्ता भारत में नहीं है या अपना कामकाज करने में मानसिक रूप से असमर्थ है वहां ऐसे कुटुंब के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(ग) किसी लंपनी या स्थानीय प्राधिकरण की दशा में, उसके प्रधान अधिकारी द्वारा ;

(घ) किसी फर्म की दशा में, उसके किसी ऐसे भागीदार द्वारा जो अवयस्क नहीं है ;

(ड) किसी अन्य संगम की दशा में, संगम के किसी सदस्य या उसके प्रधान अधिकारी द्वारा; और

(व) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, उस व्यक्ति या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति द्वारा ।

(3) प्रत्येक आवेदन प्रारूप एससी (एसटी)-1 पांच प्रतियों में फाइल किया जाएगा और उसके साथ एक हजार रूपए की फीस होगी ।

(4) सेवाकर नियम 1994 (जिसे इसके पश्चात टीआर - 6 चालान भी कहा गया है) के अधीन आवेदक द्वारा स्वीकार की गई सेवा कर की अतिरिक्त रकम उस पर देय ब्याज सहित उसके द्वारा पांच प्रतियों में टीआर - 6 चालान या जी.ए.आर. 7 के अधीन किसी प्राधिकृत बैंक में जमा की जाएगी ।

**4. मामलों के समझौते** के लिए आवेदन में जानकारी का प्रकटन—समझौता आयुक्त, अधिनियम की धारा 83 द्वारा सेवा कर को लागू की गई उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32च की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क या सेवा कर आयुक्त से रिपोर्ट मंगाते समय नियम 3 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन, आवेदन के उपाबंध और ऐसे उपाबंध से संलग्न विवरणों और अन्य दस्तावेजों की एक प्रति अग्रेषित करेगा ।

**5. संपत्ति की अनंतिम कुर्की की रीति—**(1) जहां समझौता आयोग, अधिनियम की धारा 83 द्वारा सेवा कर को लागू की गई उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32छ की उपधारा (1) के अधीन संपत्ति की कुर्की का आदेश करता है वहां वह ऐसे आदेश की एक प्रति, उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर आयुक्त को भेजेगा, जिसमें आवेदक किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का स्वामी है या निवास करता है या अपना कारबाहर चलाता है या उसका बैंक खाता है ।

(2) आयुक्त, उपनियम (1) में निर्दिष्ट आदेश प्राप्त होने पर, उसके अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी को, जो सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क या सेवा कर की पंक्ति से नीचे का न हो, आवेदक की ऐसी संपत्ति को कुर्क करने के कदम उठाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(3) उपनियम (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी, कुर्क की गई संपत्ति की सूची तैयार करेगा और उसमें, स्थावर संपत्ति की दशा में, ऐसी संपत्ति के ऐसे वर्णन, जो उसकी पहचान करने के लिए पर्याप्त है और जंगम संपत्ति की दशा में, वह स्थान विनिर्दिष्ट करेगा जहां ऐसी संपत्ति निविष्ट है या

रखी गई है और उसकी एक प्रति आवेदक या ऐसे व्यक्ति को जिसके प्रभार से संपत्ति कुर्क की जाती है, सौंप देगा।

(4) अधिनियम (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी इस प्रकार तैयार की गई सूची की एक प्रति केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त और समझौता आयोग को भेजेगा।

**6. रिपोर्टों की प्रतियों के लिए फीस—कोई व्यक्ति, जो अधिनियम की धारा 83 द्वारा सेवा कर को लागू की गई उत्पाद-शुल्क की धारा 32अ के अधीन किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों की प्रतियां अभिप्राप्त करने के लिए कोई आवेदन करता है, प्रत्येक रिपोर्ट के एक पृष्ठ या उसके किसी भाग के लिए पांच रुपए की फीस संदर्भ करेगा।**

#### प्ररूप सं0 एससी (एसटी)-1

[सेवा कर (मामलों का समझौता) नियम, 2012 का नियम 3 देखिए]

स्थित सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समझौता आयोग की \_\_\_\_\_ न्यायपीठ के समक्ष

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 द्वारा सेवा कर को लागू की गई केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32अ के अधीन किसी मामले के समझौते के लिए आवेदन का प्ररूप

|    |  |
|----|--|
| 1. | आवेदक का पूरा नाम :  |
| 2. | (i) आवेदक का डाक पता :<br><br>(ii) आवेदक का ई-मेल पता, यदि कोई है :  |
| 3  | (i) पत्र व्यवहार के लिए पता :<br><br>(ii) टेलीफोन संख्या :   |
| 4. | (i) स्थायी लेखा संख्यांक :<br><br>(ii) सेवा कर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक :<br><br>(iii) प्रास्थिति : (टिप्पण 2 देखिए) :  |
| 5. | (i) आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क/सेवा कर आयुक्त :<br><br>(ii) आवेदक पर अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क/सेवा कर आयुक्त का डाक पता : |
| 6. | आवेदक को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के ब्यौरे—<br><br>(क) कारण बताओ नोटिस सं0 और तारीख :  |

1926 927/12-4

|     |  |
|-----|--|
|     | <p>(ख) नोटिस में विवाद की अवधि :</p> <p>(ग) नोटिस में मांगा गया सेवा कर (रूपयों में) :</p> <p>(घ) वह विवाद, जिसके संबंध में समझौते के लिए आवेदन किया गया है :</p> <p>(ङ) वह न्यायनिर्णयन प्राधिकारी जिसके समक्ष नोटिस, न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है :</p>  |
| 7.  | <p>(i) क्या विवाद की अवधि के लिए सेवा कर विवरणियां फाइल की गई थीं :</p> <p style="padding-left: 2em;">(ii) क्या कराधेय सेवाओं के बीजकों को लेखा बहियों में सम्यक् रूप से प्रविष्ट किया गया है, यदि ऐसा है, तो उसके ब्यौरे :</p> <p><b>टिप्पणि :</b> सुसंगत सेवा कर विवरणियों और लेखा बहियों/रजिस्टर से उद्धरणों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाएं।</p>   |
| 8.  | मामले के संक्षिप्त तथ्य और समझौता कराए जाने वाले विवाद्यकों की विशिष्टियां आवेदक द्वारा मांगी समझौते की शर्तें :   |
| 9.  | <p>(क) सेवा कर की रकम, जो समझौते के लिए संदेय के रूप में स्वीकार की गई है (रूपयों में)</p> <p>(ख) उक्त स्वीकृत सेवा कर पर ब्याज (रूपयों में) :</p> <p>(अनुबंध I में उपरोक्त (क) और (ख) की गणना का संलग्न विस्तार)</p>  |
| 10. | आवेदक द्वारा स्वीकृत सेवा कर, ऊपर (9) पर ब्याज सहित संदाय ब्यौरे टीआर 6 या जी.ए.आर. 7 चालान संख्या और तारीख) (अनुबंध II में संलग्न विस्तार) :  |
| 11. | <p>क्या आवेदक द्वारा समझौता आयोग की किसी न्यायपीठ के समक्ष समझौते के लिए कोई आवेदन (प्रत्युत आवेदन से भिन्न) फाइल किया गया है, यदि हाँ तो निम्नलिखित जानकारी दी जाए :</p> <p>(क) आवेदन संख्या और तारीख :</p> <p>(ख) सेवा कर की स्वीकृत रकम</p> <p>(ग) कारण बताओ नोटिस संख्या और तारीख :</p> <p>(घ) आवेदन की प्रास्थिति, यदि विनिश्चित किया गया है तब आयोग के अंतिम आदेश का विवरण :</p> <p style="padding-left: 2em;">(i) समझौता आदेश संख्या और तारीख :</p> <p style="padding-left: 2em;">(ii) समझौता रकम के निक्षेप के ब्यौरे :</p> <p style="padding-left: 2em;">(iii) चाहे आदेश की शर्तें पर समझौता राशि का भुगतान किया गया है</p> <p>(ङ.) यदि समझौता आयोग द्वारा आवेदक के किसी आवेदन को वापस भेजा था/अस्वीकार</p> |

|     |   |
|-----|---|
|     | किया गया था तो उस आदेश का संदर्भ सं0 और तारीख बताएं<br><br>(च) अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत आवेदक यदि किसी भी अपराध के मामले के संबंध में समझौता आयोग द्वारा दोषी ठहराया गया हो तो उस आदेश का संदर्भ सं0 और तारीख बताएं   |
| 12. | (i) अधिनियम की धारा 83 द्वारा सेवा कर को लागू की गई उत्पाद अधिनियम की धारा 32-ओ के अंतर्गत समझौता आयोग की किसी भी बैंच ने यदि आवेदक को कभी आगे आवेदन करने से वंचित किया गया था तो उस आदेश का विवरण दें।<br><br>(ii) सेवा कर अधिनियम की धारा 83 द्वारा को लागू की गई उत्पाद अधिनियम की धारा 32ज्ञ के अंतर्गत समझौता आयोग की किसी भी बैंच ने यदि आवेदक के साथ धारा के तहत समझौता किया है तो उस आदेश का विवरण दें। |

आवेदक के हस्ताक्षर

## सत्यापन

मैं, \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री/पत्नी \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं \_\_\_\_\_ के रूप में अपनी हैसियत में यह आवेदन कर रहा हूं/कर रही हूं और मैं इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं।

यह कि इस आवेदन की अन्तर्वस्तुएं सही हैं और मैंने अधिनियम की धारा 83 द्वारा सेवा कर को लागू किए गए उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अध्याय V के उपबंधों के उल्लंघन में समझौता आयोग के समक्ष समझौते के लिए कोई आवेदन फाइल नहीं किया है और यह भी कि मामले के तथ्यों की किसी सुसंगत जानकारी को छिपाया नहीं गया है। आवेदन से संलग्न सभी दस्तावेजों के उपाबंध मूल की सत्य प्रतिलिपियां हैं और वित्तीय संव्यवहार दर्शित करने वाली सारणियां सही हैं और सम्यक् रूप से मेरे द्वारा प्रमाणित हैं।

यह कि उस मामले की बाबत जिसके लिए समझौते की ईप्सा की जा रही है, कोई कार्यवाही यथास्थिति, आयुक्त (अपील), सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण या न्यायालयों के समक्ष लंबित नहीं है या उक्त अपील प्राधिकारियों द्वारा न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित नहीं की गई है।

आज तारीख \_\_\_\_\_ मास \_\_\_\_\_ वर्ष \_\_\_\_\_ को \_\_\_\_\_ में (स्थान उल्लिखित करें) सत्यापित किया गया

अभिसाक्षी

**टिप्पण :**

आवेदन फीस प्राधिकृत बैंक की किसी शाखा या भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा या भारतीय रिजर्व बैंक की किसी शाखा में जमा की जानी चाहिए और चालान की तीसरी प्रति आवेदन के साथ समझौता आयोग को भेजी जानी चाहिए। समझौता आयोग चैक, ड्राफ्ट, हुंडी या अन्य प्रक्राम्य लिखतों को स्वीकार नहीं करेगा।

2. कृपया बताएं कि क्या व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी, फर्म, व्यक्ति संगम आदि हैं।
3. आवेदन की मद 9 में निर्दिष्ट संदेय के रूप में स्वीकृत सेवा कर की अतिरिक्त रकम और उस पर देय ब्याज के ब्यौरे इस आवेदन के उपाबंध में दिए जाएंगे।
4. मद 9 में निर्दिष्ट समझौते के लिए संदेय के रूप में स्वीकृत सेवा कर की रकम और उस पर देय ब्याज उपर्देशित करते हुए टीआर - 6 चालान की, मूल प्रति आवेदक द्वारा रखी जाएगी, दूसरी प्रति आवेदक पर अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को पृष्ठांकित की जाएगी, तीसरी प्रति यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क या सेवा कर आयुक्त कार्यालय के अधिकारिता रखने वाले मुख्य लेखा अधिकारी को पृष्ठांकित की जाएगी, चौथी प्रति बैंक में रखी जाएगी और पांचवी प्रति इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी। जी.ए.आर. 7 के मामले में, क्षेत्राधिकार केन्द्रीय आबकारी द्वारा सत्यापित, करदाता फोटो प्रति प्रतिपर्ण है, विभिन्न अधिकारियों को सुसज्जित किया जा सकता है।

**उपाबंध**

अधिनियम की धारा 83 द्वारा सेवा कर को लागू की गई केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 32ड (1) के अधीन किए गए आवेदन की मद 8 में निर्दिष्ट विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करने वाला विवरण

1. उस जानकारी का ब्यौरा, जिसे कालिक विवरणी में सही रूप से घोषित नहीं किया गया है।
2. जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में मांगे गए कुल सेवा कर में से स्वीकार किया गया सेवा कर दायित्व और वह रीति, जिसमें ऐसा सेवा कर दायित्व व्युत्पन्न हुआ है।
3. आवेदक द्वारा ईस्पित समझौते के निबंधनों सहित समझौता कराए जाने वाले विवाद्यकों के संबंध में तथ्यों का पूर्ण और सही प्रकटन।

**स्थान :**

आवेदक के हस्ताक्षर

**तारीख :**

[फा. सं. 334/1/2012-(एसटी)]  
राजकुमार दिविजय, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th May, 2012

**No. 16/2012- Service Tax**

**GS.R. 403(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as “the Act”), read with sections 31, 32 and 32A to 32P of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) made applicable to service tax vide section 83 of the Act, 1994, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

**1. Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Service Tax (Settlement of Cases) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means Chapter V of the Finance Act, 1994 (32 of 1994);
- (b) “Excise Act” means the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944);
- (c) “Form SC(ST)-1” means the form appended to these rules;
- (d) “section” means a section of the Act ;
- (e) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act or Excise Act, shall have the respective meanings assigned to them in those Acts.

**3. Form and manner of Application.** - (1) An application under sub-section (1) of section 32E of Excise Act, made applicable to service tax vide section 83 of the Act, shall be made in the Form SC(ST)-1.

(2) The application referred to in sub-rule (1), the verification contained therein and all relevant documents accompanying such application shall be signed,-

(a) in the case of an individual, by the individual himself or where the individual is absent from India, by the individual concerned or by some person duly authorised by him in this behalf; and where the individual is a minor or is mentally incapacitated from attending to his affairs, by his guardian or by any other person competent to act on his behalf;

(b) in the case of a Hindu undivided family, by the *Karta* of such family and, where the *Karta* is absent from India or is mentally incapacitated from attending to his affairs, by the senior most adult member of the family available;

(c) in the case of a company or local authority, by the principal officer thereof;

(d) in the case of a firm, by any partner thereof, not being a minor;

1926 95712-5

(e) in case of any other association, by any member of the association or the principal officer thereof; and

(f) in the case of any other person, by that person or some person competent to act on his behalf.

(3) Every application in the Form SC(ST)-1 shall be filed in quintuplicate and shall be accompanied by a fee of one thousand rupees.

(4) The additional amount of service tax accepted by the applicant along with interest due thereon, shall be deposited by him in any of the authorised bank under TR-6, referred to in the Service Tax Rules, 1994 (hereinafter referred to as TR-6 Challan) in quintuplicate, or G.A.R.-7 and shall be disclosed by him in the Form.

**4. Disclosure of information in the application for settlement of cases.** - The Settlement Commission shall, while calling for a report from the Commissioner of Central Excise having jurisdiction or Commissioner of Service Tax having jurisdiction, under sub-section (3) of section 32F of Excise Act, made applicable to service tax vide section 83 of the Act, forward a copy of the application referred to in sub-rule (1) of rule 3 along with the annexure to the application and the statements and other documents accompanying such annexure.

**5. Manner of provisional attachment of property.** - (1) Where the Settlement Commission orders attachment of property under sub-section (1) of section 32G of Excise Act, made applicable to service tax vide section 83 of the Act, it shall send a copy of such order to the Commissioner of Central Excise or Commissioner of Service Tax having jurisdiction over the place in which the applicant owns any movable or immovable property or resides or carries on his business or has his bank account.

(2) On receipt of the order referred to in sub-rule (1), the Commissioner may authorise any officer subordinate to him and not below the rank of an Assistant Commissioner of Central Excise or Service Tax to take steps to attach such property of the applicant.

(3) The officer authorised under sub-rule (2) shall prepare an inventory of the property attached and specify in it, in the case of the immovable property, the description of such property sufficient to identify it and in case of the movable property, the place where such property is lodged or kept and shall hand over a copy of the same to the applicant or to the person from whose charge the property is attached.

(4) The officer authorised under sub-rule (2) shall send a copy of the inventory so prepared each to the Commissioner of Central Excise and the Settlement Commission.

**6. Fee for copies of reports.** — Any person who makes an application under section 32J of Excise Act, made applicable to service tax vide section 83 of the Act, for obtaining copies of reports made by any Central Excise Officer, shall pay a fee of five rupees per page of each report or part thereof.

Form No. SC(ST)-1

[See rule 3 of the Service Tax (Settlement of Cases) Rules, 2012]

**Before the Customs and Central Excise Settlement Commission  
Bench at \_\_\_\_\_**

**Form of application for settlement of a case under section 32E of Excise Act made applicable to service tax vide section 83 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994)**

|    |   |
|----|---|
| 1. | Full name of the applicant:   |
| 2. | (i) Postal address of the applicant<br>(ii) E-mail address of the applicant, if any   |
| 3. | (i) Address for communication:<br>(ii) Telephone No.  |
| 4. | (i) Permanent Account No:<br>(ii) Service Tax registration No:<br>(iii) Status: (See note 2)  |
| 5. | (i) Commissioner of Central Excise/Service Tax having jurisdiction over the applicant:<br>(ii) Postal address of the Commissioner of Central Excise/Service Tax having jurisdiction over the applicant:   |
| 6. | Details of Show Cause Notice issued to the applicant<br>(a) Show Cause Notice No and date<br>(b) Period of dispute in the notice<br>(c) Service tax demanded in the notice ( in Rs. )<br>(d) Dispute in connection with which the application for settlement is made.<br>(e) Adjudicating authority before whom the notice is pending adjudication. |
| 7. | (i) Whether service tax returns were filed for the period of dispute:<br>(ii) Whether the invoices on taxable services are duly entered in the books of accounts. If so, details thereof.<br><b>Note:</b> Self-attested copies of relevant service tax returns and extracts from books of accounts/register to be enclosed.                         |
| 8. | Brief facts of the case and particulars of the issues to be settled and terms of settlement sought by the applicant:  |
| 9. | (a) Amount of service tax accepted as payable for settlement (in Rs)<br>(b) Interest on the said admitted service tax (in Rs.):<br>(Detailed calculations of (a) and (b) above to be enclosed as Annexure-I)  |

|     |  |
|-----|--|
| 10. | Payment details of the service tax accepted, by the applicant, along with interest as at (9) above (TR-6 challan or G.A.R.-7 number and date)<br>(Details to be enclosed as Annexure-II)   |
| 11. | Whether any application for settlement (other than the present one) has been filed by the applicant before any Bench of Settlement Commission. If yes, the following information may be provided :<br>(a) Application No. and date<br>(b) Amount admitted for settlement<br>(c) Show cause notice No. and date<br>(d) Status of the application, if decided, then details of the final order of the Commission:<br>(i) Settlement order No. and date<br>(ii) Details of deposit of settlement amount<br>(iii) Whether settlement amount has been paid in terms of the order<br>(e) If any application of the applicant was sent back/rejected by the Settlement Commission, the reference number and date of the order<br>(f) Reference number and date of the order, if any, in case the applicant was convicted of any offence under Chapter V of the Act in relation to a case settled earlier by the Settlement Commission |
| 12. | (i) Details of the order, if the applicant was ever debarred from making further application for settlement under section 32-O of Excise Act made applicable to Service Tax vide section 83 of the Act, by any of the Benches of the Settlement Commission<br>(ii) Details of the order, if any settlement in respect of the applicant has ever been made void under section 32L of Excise Act made applicable to Service Tax vide section 83 of the Act, by any of the Benches of the Settlement Commission   |

Signature of the applicant

**VERIFICATION**

I.....son/daughter/wife of ..... residing at..... do solemnly declare that I am making this application in my capacity as.....and I am competent to verify it.

That the contents of this application are true and that I have not filed any application for settlement in contravention of the provisions of the Chapter V of Excise Act made applicable to service tax vide section 83 of the Act, before the Settlement Commission and also that no information relevant to the facts of the case has been suppressed. Annexures of the documents accompanying the application are true copies of the originals and the tables showing financial transaction are correct and are duly attested by me.

That no proceeding in respect of the case for which settlement is being sought, is pending before Commissioner (Appeal), Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal or the courts, as

the case may be, or has been remanded back to the adjudicating authority by the said appellate authorities.

Verified today the.....day of.....(mention the month and year) at .....(mention the place)

Note:

Deponent

1. The application fee should be credited in a branch of the authorised bank or a branch of the State Bank of India or a branch of Reserve Bank of India and the triplicate copy of the challan sent to the Settlement Commission with the application. The Settlement Commission will not accept cheques, drafts, hundies or other negotiable instruments.
2. Please state whether individual, Hindu undivided family, company, firm, an association of persons, etc.
3. Details of the additional amount of Service Tax accepted as payable and interest thereon referred to in item 9 of the application shall be furnished in annexure to this application.
4. Original copy of the TR-6 challan indicating amount of service tax accepted as payable for settlement and interest thereon referred to in item 9 be retained by the applicant, duplicate be endorsed to the Central Excise Officer having jurisdiction over the applicant, triplicate be endorsed to the jurisdictional Chief Accounts Officer of the Central Excise or Service Tax Commissionerate as the case may be, quadruplicate be retained by the bank and quintuplicate copy be enclosed with this application form. In the case of G.A.R.-7, photocopies of tax payer's counterfoil, attested by the jurisdictional Central Excise Officer, may be furnished to various authorities.

#### ANNEXURE

Statement containing particulars, referred to in item 8 of the application, made under section 32E (1) of Excise Act made applicable to service tax vide section 83 of the Act.

1. Details of information which has not been correctly declared in the periodical return;
2. Service tax liability accepted out of the total service tax demanded in the show cause notice issued and the manner in which such service tax liability has been derived;
3. Full and true disclosure of the facts regarding the issues to be settled including the terms of settlement sought for by the applicant.

Signature of the applicant

Place :

Date :

1926-5-7-12-6

[F. No. 334/1/2012-(ST)]

RAJ KUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2012

सं. 17/2012-सेवा-कर

सा.का.नि. 404(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “अधिनियम” कहा गया है) की धारा 94 की उपधारा (2) के खंड (झ) के साथ पठित अधिनियम की धारा 83 द्वारा सेवा कर को लागू बनाते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 9क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

## 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेवा कर (अपराधों का शमन) नियम, 2012 है।
- (2) ये वित्त अधिनियम, सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

## 2. परिभाषाएँ :- इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “अधिनियम” से वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) का अध्याय 5 अभिप्रेत है;
- (ख) “आवेदक” से कोई निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है किन्तु सेवा कर नियम, 1994 के नियम 3 के अधीन अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 3 के अधीन बोर्ड या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा नियुक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी सम्मिलित नहीं होंगे;
- (ग) “शमन प्राधिकारी” से ऐसे स्थान पर अधिकारिता रखने वाला मुख्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त अभिप्रेत है जहां अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है या किया जाना अभिकथित है;
- (घ) “उत्पाद अधिनियम” का अर्थ केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 (1944 का 1) है;
- (ङ) “प्ररूप” से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;
- (च) “रिपोर्टिंग प्राधिकारी” से ऐसे स्थान पर, जहां अधिनियम के अधीन अपराध किए गए हैं या किया जाना अभिकथित है, अधिकारिता रखने वाला केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क या सेवा कर आयुक्त या ऐसे स्थान पर, जहां अधिनियम के अधीन ऐसे अपराध किए गए हैं या किया जाना अभिकथित है, अधिकारिता रखने वाले मुख्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा इस बाबत यथा ‘प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है;
- (छ) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है; और

(ज) ऐसे शब्द या पद, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो, यथास्थिति, अधिनियम या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 में हैं।

**3. आवेदन का प्रस्तुप और रीति :-** कोई आवेदक अभियोजन के संरक्षण के पूर्व या इसके पश्चात् अपराध का शमन करने के लिए शमन प्राधिकारी को इन नियमों से उपाबद्ध प्रस्तुप में अधिनियम की धारा 83 द्वारा सेवा कर को लागू बनाए गए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 9क के उपधारा (2) के अधीन आवेदन कर सकेगा।

**रपष्टीकरण--** जहां अधिनियम के अधीन कोई अपराध, एक से अधिक शमन प्राधिकारी की अधिकारिता के अधीन आने वाले एक से अधिक स्थान पर किया गया है वहां ऐसे स्थान पर अधिकारिता रखने वाला मुख्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त जहां उपवंचित सेवा कर की रकम अन्य से अधिक है, सक्षम प्राधिकारी होगा।

**4. नियम 3 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया :-** (1) नियम 3 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर शमन प्राधिकारी, आवेदन में प्रस्तुत विशिष्टियों के प्रतिनिर्देश से या किसी अन्य सूचना की जो ऐसे आवेदन की परीक्षा के लिए सुसंगत समझी जाए, रिपोर्टिंग प्राधिकारी से रिपोर्ट की मांग करेगा।

(2) ऐसी रिपोर्ट शमन प्राधिकारी से संसूचना की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो शमन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात की जाए, रिपोर्टिंग प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

(3) शमन प्राधिकारी, उक्त आवेदन की अन्तर्वर्तुओं पर विचार करने के पश्चात्, नियम 5 के निबंधनानुसार शमन रकम को उपर्युक्त करते हुए, आदेश द्वारा, आवेदन मंजूर कर सकेगा और नियम 6 के निबंधनानुसार अभियोजन से उसे उन्मुक्ति दे सकेगा या ऐसा आवेदन नोमंजूर कर सकेगा :

परन्तु आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को सुने जाने का अवसर नहीं दें दिया जाता है और ऐसे नामंजूरी के आधारों का उल्लेख ऐसे आदेश में नहीं किया जाता है :

परन्तु यह और कि आवेदन, तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा, जब तक संदत्त किए जाने के लिए दायी सेवा कर, शास्ति और ब्याज, उस मामले के लिए संदत्त नहीं की गई है जिसके लिए आवेदन किया गया है।

(4) उपनियम (3) के अधीन प्रत्येक आदेश की प्रति, आवेदक को भेजी जाएगी।

(5) आवेदक, अपराधों के शमन को अनुज्ञात करने वाले उपनियम (3) के अधीन आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर शमन प्राधिकारी द्वारा संदत्त किए जाने के लिए आदेशित शमन रकम को संदत्त करेगा और शमन प्राधिकारी को ऐसे संदाय का सबूत प्रस्तुत करेगा।

(6) एक बार संदत्त शमन रकम का प्रतिदाय, ऐसे मामलों के सिवाय नहीं किया जाएगा जहां न्यायालय, अभियोजन से उन्मुक्ति की मंजूरी से इंकार करता है।

(7) आवेदक, साधिकार द्वारा दावा नहीं कर सकता है कि उसके अपराध का शमन किया जाए।

**5. शमन रकम का नियतन :-** अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपराधों के शमन के प्रयोजन के लिए शमन रकम, निम्नलिखित सारणी के उपबंध के अनुसार होगी, अर्थात् :-

## सारणी

| क्रम सं० | अपराध  | शमन रकम  |
|----------|--|--|
| (1)      | (2)  | (3)  |
| 1.       | अधिनियम की धारा 89(1)(क) के अधीन विनिर्दिष्ट अपराध | कर अपवंचन के न्यूनतम दस प्रतिशत के अधीन रहते हुए सेवा कर अपवंचन की रकम के पचास प्रतिशत तक ।  |
| 2.       | अधिनियम की धारा 89(1)(ख) के अधीन विनिर्दिष्ट अपराध | उक्त रकम के न्यूनतम दस प्रतिशत के अधीन रहते हुए, सदोष लिए गए या उपयोग किए गए सेनवेट प्रत्यय की रकम के पचास प्रतिशत तक ।                                |
| 3.       | अधिनियम की धारा 89(1)(ग) के अधीन विनिर्दिष्ट अपराध | प्रथम अपराध के लिए पचास हजार रुपए और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए इस रकम के सौ प्रतिशत द्वारा बढ़ाया जाए ।                                       |
| 4.       | अधिनियम की धारा 89(1)(घ) के अधीन विनिर्दिष्ट अपराध | प्रत्येक मास, जिसके लिए रकम को इस प्रकार जमा नहीं किया गया है, न्यूनतम दो प्रतिशत के अधीन रहते हुए, जमा न किए गए सेवा कर की रकम के पच्चीस प्रतिशत तक । |

परन्तु यदि किसी व्यक्ति ने उसी माल की बाबत उपरोक्त विनिर्दिष्ट एक से अधिक प्रवर्ग के अधीन आने वाले अपराध किए हैं और सदोषतः ली गई या उपयोग की गई सेवा कर अपवंचन की रकम या सेनवेट प्रत्यय की रकम ऐसे सभी अपराधों के लिए एक जैसी है तो ऐसे मामलों में शमन रकम जो ऐसे अपराध के लिए ऐसी रकम होगी जिसके लिए उच्चतर शमन रकम विहित की गई है ।

**6. अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करने के लिए शमन प्राधिकारी की शक्ति :-** शमन प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने इन नियमों के अधीन अपराध का शमन करने के लिए आवेदन किया है, उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है और मामले से संबंधित तथ्यों का पूरा और सही प्रकटन किया है तो ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, अपराध के शमन के अधीन आने वाले मामले की बाबत अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा ।

**7. कतिपय शर्तों में अभियोजन से उन्मुक्ति का प्रत्याहरण :-** (1) नियम 6 के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई उन्मुक्ति प्रत्याहृत हो जाएगी यदि ऐसा व्यक्ति शमन प्राधिकारी द्वारा पारित शमन आदेश में विनिर्दिष्ट कोई रकम ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन संदाय करने में असफल रहता है या ऐसी किसी अन्य शर्त का जिसके अधीन रहते हुए उन्मुक्ति दी गई है, अनुपालन करने में असफल रहता है और तदुपरि अधिनियम के उपर्युक्त ऐसे लागू होंगे मानो ऐसी कोई उन्मुक्ति नहीं दी गई थी ।

(2) उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई उन्मुक्ति, किसी समय, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्याहत की जा सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने शमन कार्यवाहियों के अनुक्रम में किन्हीं तत्त्विक विशिष्टियों को छिपाया था या मिथ्या साक्ष्य दिया था और तदुपरि ऐसे व्यक्ति का विचारण उस अपराध की बाबत किया जा सकेगा जिसके लिए उन्मुक्ति दी गई थी या किसी अन्य अपराध के लिए जिसके लिए यह प्रतीत होता है कि यह उसके द्वारा शमन कार्यवाहियों के संबंध में किया गया है और तदुपरि अधिनियम के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो ऐसी कोई उन्मुक्ति नहीं दी गई थी ।

प्रश्नप  
(नियम 3 देखिए)

अपराध के शमन करने का आवेदन

1. आवेदक का पूरा नाम और स्थायी पता :
2. संसूचना का पता :
3. (i) स्थायी खाता संख्या (पैन) :  
(ii) सेवा कर रजिस्ट्रीकरण संख्या :
4. आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क/सेवा कर आयुक्त :
5. वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V का विनिर्दिष्ट उपबंध जिसके अतिक्रमण के विरुद्ध अभियोजन संस्थित किया गया है या अनुध्यात है जिसके लिए शमन करने का आवेदन फाइल किया जा रहा है ।
6. शमन करने के संबंध में बीजकों/ न्यायनिर्णयन आदेश के ब्यौरे :
7. मामले के संक्षिप्त तथ्य और आरोपित अपराध (अपराधों) का ब्यौरा :
8. क्या कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है :
9. यदि हाँ, मांगे गए सेवा कर के ब्यौरे :
10. क्या कारण बताओ नोटिस का न्यायनिर्णयन किया गया है :
11. यदि हाँ, न्यायनिर्णयन के ब्यौरे :
  - (क) पुष्ट सेवा कर की रकम :
  - (ख) वर्सूल/इंकार किए जाने वाले सेनेवेट प्रत्यय की रकम :
  - (ग) अधिरोपित शास्ति :
12. क्या यह वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के अधीन प्रथम अपराध है, यदि हाँ तो पूर्व मामलों के ब्यौरे :
13. क्या उसी अपराध के लिए कोई कार्यवाही किसी अन्य विधि के अधीन अनुध्यात है, यदि हाँ तो उसके ब्यौरे :

1926 ५/७/१२-७

आवेदक का नाम और उसके हस्ताक्षर

**घोषणा**

मैं, सेवा कर (अपराधों का शमन) नियम, 2012 के नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन शमन प्राधिकारी द्वारा यथानियत शमन रकम का संदाय करूँगा।

2. मैं समझता हूँ कि मैं साधिकार यह दावा नहीं कर सकता हूँ कि अधिनियम के अधीन मेरे द्वारा किए गए अपराध का शमन किया जाना चाहिए।

आवेदक का नाम और उसके हस्ताक्षर

**सत्यापन**

मैं, \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री/पत्नी \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं \_\_\_\_\_ के रूप में अपनी हैसियत में यह आवेदन कर रहा हूँ/कर रही हूँ और मैं इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ। इस आवेदन की अन्तर्वस्तुएं मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में सही हैं और मामले के तथ्यों की किसी सुसंगत जानकारी को छिपाया नहीं गया है। आवेदन से संलग्न दस्तावेज मूल की सत्य प्रतियां हैं और वित्तीय संबंधहारों को दर्शित करने वाली सारणियां सही हैं और सम्यक् रूप से मेरे द्वारा प्रमाणित हैं।

आज तारीख \_\_\_\_\_ मास \_\_\_\_\_ वर्ष \_\_\_\_\_ को सत्यापित किया गया।

स्थान :

आवेदक का नाम और उसके हस्ताक्षर

तारीख :

[फा. सं. 334/1/2012-एसटी]  
राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th May, 2012

No. 17/2012- Service-Tax

**G.S.R. 404(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994)(hereinafter referred to as “the Act”) read with sub-section (2) of section 9A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), made applicable to service tax vide section 83 of the Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely :

**1. Short title and commencement.-**

- (1) These rules may be called the Service Tax (Compounding of Offences) Rules, 2012.
- (2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means Chapter V of the Finance Act, 1994 (32 of 1994);
- (b) “applicant” means any assessee or any other person, but shall not include officers of Central Excise appointed for exercising the powers under the Act under rule 3 of the Service Tax Rules, 1994;
- (c) “compounding authority” means the Chief Commissioner of Central Excise, having jurisdiction over the place where the offence under the Act, have been or alleged to have been committed;
- (d) “Excise Act” means the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944);
- (e) “form” means the form appended to these rules;
- (f) “reporting authority” means, the Commissioner of Central Excise or Commissioner of Service Tax, having jurisdiction over the place where the offences under the Act have

been or are alleged to have been committed or any other officer as may be authorised in this regard by the Chief Commissioner of Central Excise having jurisdiction over the place where such offences under the Act, have been or are alleged to have been committed;

- (g) "section" means a section of the Act; and
- (h) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act or Central Excise Act, 1944 shall have the respective meanings assigned to them in the Act or Central Excise Act, 1944, as the case may be.

**3. Form and manner of application.**— An applicant may, either before or after the institution of prosecution, make an application under sub-section (2) of section 9A of Excise Act, made applicable to service tax vide section 83 of the Act, in the form appended to these rules, to the compounding authority to compound the offence.

**Explanation.**— Where an offence under the Act has been committed at more than one place falling under the jurisdiction of more than one compounding authority, then the Chief Commissioner of Central Excise having jurisdiction over such place where the amount of service tax evaded is more than the others, shall be the competent authority.

**4. Procedure on receipt of application under rule 3.**— (1) On receipt of an application under rule 3, the compounding authority shall call for a report from the reporting authority with reference to the particulars furnished in the application, or any other information, which may be considered relevant for examination of such application.

(2) Such report shall be furnished by the reporting authority within a period of one month or within such extended period as may be allowed by the compounding authority, from the date of receipt of communication from the compounding authority.

(3) The compounding authority, after taking into account the contents of the said application, may, by order, either allow the application indicating the compounding amount in terms of rule 5 and grant him immunity from prosecution in terms of rule 6 or reject such application:

**Provided** that application shall not be rejected unless an opportunity has been given to the applicant of being heard and the grounds of such rejection are mentioned in such order:

**Provided further** that application shall not be allowed unless the service tax, penalty and interest liable to be paid have been paid for the case for which application has been made.

- (4) A copy of every order under sub-rule (3) shall be sent to the applicant.
- (5) The applicant shall, within a period of thirty days from the date of receipt of order under sub-rule (3) allowing the compounding of offences, pay the compounding amount, as ordered to be paid by the compounding authority and shall furnish the proof of such payment to the compounding authority.
- (6) The compounding amount once paid shall not be refunded except in cases where the court rejects grant of immunity from prosecution.
- (7) The applicant shall not claim, as of right, that his offence be compounded.

**5. Fixation of the compounding amount.** - For the purpose of compounding of offences under the provisions of the Act, the compounding amount shall be as provided in the following Table, namely:-

TABLE

| S.<br>No. | Offence<br>(2)                                       | Compounding amount<br>(3)  |
|-----------|--|--|
| 1.        | Offence specified under section 89 (1)(a) of the Act | Up to fifty per cent. of the amount of service tax evasion, subject to minimum of ten per cent. of amount of tax evaded.   |
| 2.        | Offence specified under section 89 (1)(b) of the Act | Upto fifty per cent. of the amount of CENVAT Credit wrongly taken or utilised, subject to minimum of ten per cent. of said amount.   |
| 3.        | Offence specified under section 89 (1)(c) of the Act | Rupees fifty thousand for the first offence and to be increased by hundred per cent. of this amount for each subsequent offence.   |
| 4.        | Offence specified under section 89 (1)(d) of the Act | Upto twenty five per cent. of the amount of service tax not deposited subject to a minimum of two per cent. for each month for which the amount has not been so deposited. |

Provided that if a person has committed offences falling under more than one category specified above and where the amount of service tax evasion or amount of CENVAT Credit wrongly taken or utilised is the same for all such offences, the compounding amount, in such

1926 5/7/2-8

cases, shall be the amount as determined for the offence for which a higher compounding amount has been prescribed.

**6. Power of compounding authority to grant immunity from prosecution.** - The compounding authority, if he is satisfied that any person who has made the application for compounding of offence under these rules has co-operated in the proceedings before him and has made full and true disclosure of facts relating to the case, grant such person, subject to such conditions as he may think fit to impose, immunity from prosecution for any offence under the Act, with respect to the case covered by the compounding of offence.

**7. Withdrawal of immunity from prosecution in certain conditions.** - (1) An immunity granted to a person under rule 6 shall stand withdrawn if such person fails to pay any sum specified in the order of compounding passed by the compounding authority, under sub-rule (3) of rule 4 within the time specified in the order or fails to comply with any other condition subject to which the immunity was granted and thereupon the provisions of the Act, shall apply as if no such immunity had been granted.

(2) An immunity granted to a person under sub-rule (1) may, at any time, be withdrawn by the compounding authority, if he is satisfied that such person had, in the course of the compounding proceedings, concealed any material particulars, or had given false evidence, and thereupon the person may be tried for the offence with respect to which immunity was granted or for any other offence that appears to have been committed by him in connection with the compounding proceedings and, thereupon, the provisions of the Act, shall apply as if no such immunity had been granted.

**FORM**  
(See rule 3)

**Application for Compounding of Offence**

1. Full Name and permanent address of the applicant:
2. Address for communication:
3. (i) Permanent Account Number (PAN):  
(ii) Service Tax Registration No:
4. Commissioner of Central Excise/Service Tax having jurisdiction over the applicant:
5. Specific provision(s) of Chapter V of the Finance Act, 1994, against whose violation, prosecution is instituted or contemplated for which application of compounding is being filed:
6. Details of Adjudication Order in relation to the case for compounding:
7. Brief facts of the case and particulars of the offence (s) charged:
8. Whether Show Cause Notice issued:
9. If yes; details of service tax demanded:
10. Whether Show Cause Notice has been adjudicated:
11. If yes, adjudication details:  
(a) Amount of service tax confirmed:  
(b) Amount of CENVAT credit to be recovered/denied:  
(c) Penalty imposed:
12. Whether this is the first offence under Chapter V of the Finance Act, 1994, if not, details of previous cases:
13. Whether any proceedings for the same offence contemplated under any other law, if so, the details thereof:

Name and Signature of the applicant.

**DECLARATION**

1. I shall pay the compounding amount, as may be fixed by the compounding authority under sub-rule (3) of rule 4 of the Service Tax (Compounding of Offences) Rules, 2012.
2. I understand that I shall not claim, as of right that the offence committed by me under the Act be compounded.

Name and Signature of the applicant.

**VERIFICATION**

I, \_\_\_\_\_ son/daughter/wife of \_\_\_\_\_ residing at \_\_\_\_\_ do solemnly declare that I am making this application in my capacity as \_\_\_\_\_ and I am competent to verify it. That the contents of this application are true to the best of my knowledge and belief and no information relevant to the facts of the case has been suppressed. The documents accompanying the application are true copies of the originals and the tables showing financial transactions are correct and are duly attested by me.

Verified today the \_\_\_\_\_ day of (month) \_\_\_\_\_ (year) at \_\_\_\_\_.

Name and Signature of the applicant.

Place:

Date:

[F. No. 334/I/2012-ST]  
RAJ KUMAR DIGVJAY, Under Secy.